tunities to the Small Scale Industrial units and improve their viability in respect of other facilities; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The Government is operating various schemes for providing marketing opportunities to small scale industrial units in order to make them viable. The important schemes are Purchase Preference of SSI products, Single Point Registration Scheme with benefit of price preference of 15%, Scheme of National Award for Quality products, Scheme of participation of SSI units in internal and international exhibitions, schemes operated by the NSIC which include buyer/seller meets, Consortia formation, Market Development Centres, etc. The State Governments are also promoting the marketing of SSI products through their State Market Development Corporations.

(b) Does not arise.

बिहार से मजदूरों का पलायन

2218. **श्री नागमणि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के भारी संख्या में गरीब मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में देश के अन्य भागों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसे बेबस और गरीब मजदूरों की संख्या के संबंध में जानकारी है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार के ऐसे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) सरकार को यह जानकारी है कि मौसमी क्रियाकलापों जैसे फसल कटाई, चावल का छिलका उतारने जैसे अस्थाई नियोजन और ईंट भट्टों में कार्य और कारखानों तथा निर्माण कार्य के लिए भी बिहार से कर्मकार अन्य राज्यों को प्रवास करते हैं। इस प्रकार से प्रवास बेहतर संभावनाओं और उच्च मजदूरी के लिए भी किया जाता है।

(ख) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मई, 1994 तक बिहार के 29 जिलों से, ठेकेदारों के माध्यम से अन्य राज्यों को प्रवास करने वाले श्रमिकों की संख्या 9,524 थी। अपनी इच्छा से प्रवास करने वाले व्यक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार रो०गा०यो०, ज०रो०यो०, ग०ज०रो०यो० (ए०ग्रा०वि० का भी) जैसे अनेक गरीबी उन्मूलक और रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिन्हें आय सृजक परिसम्पतियां प्राप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए अतिरिक्त लाभदायी रोजगार सृजित करने के लिए बनाया गया है। आठवीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में भरपूर वृद्धि की गई है।

NRI and direct foreign investment in India

2219. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total NRI investment and direct foreign investment already made and projected to be made in the country so far and in different States, particularly in Maharashtra and Madhya Pradesh;

(b) the State which has attracted the highest NRI and other foreign investment and which one has the highest potential for attracting such investment; and

(c) steps taken by the different State Governments to provide infrastructural facilities and incentives for attracting such investments especially those by Gujarat and Maharashtra?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Since the introduction of New Industrial Policy in July 1991, till 31.5.96, proposals involving Non-Resident Indian (NRI) and Foreign Direct Investment

(FDI) investment approved by Government is as under:—

	Amount (Rs. in crores)
Non-Resident Indians (NRIs)	20863.8
Foreign Direct Investment (FDI)	63140.4

Maharashtra State has attracted highest investment.

(c) The State Government formulate their own incentive schemes and update infrastructural facilities for attracting foreign investment in their States and review the same from time to time, details of which are not maintained by the Central Government.

केन्द्रीय पूल को खाद्यान्नों का अंशदान

2220. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल में प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्यान्नों की कितनी-कितनी मात्रा का अंशदान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिले में उक्त खाद्यान्नों की वास्तविक मांग कितनी थी; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की खरीद और आपूर्ति के बीच कितना अन्तर रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं और चावल की राज्यवार मात्राएं बताने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई मांग, उनकी संगत आवश्यकताएं, उठान प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में स्टाक आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटन माह-दर-माह आधार पर किए जाते हैं। खाद्यान्नों के जिला-वार आवंटन माह-दर-माह आधार पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

1995-96 की अवधि के लिए गेहूं और चावल की मांग, आवंटन और उठान बताने वाला विवरण अनुपत्र पर दिया गया है। **(देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 50)**

(घ) विपणन मौसम, 1995-96 के दौरान वसूल की गई गेहूं और चावल की मात्रा 1995-96 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों द्वारा उठाई गई मात्रा से अधिक थी।

विवरण

1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल की राज्य-वार वसूली

(लाख टन में)

राज्य	गेहूं (रबी विपणन मौसम)	चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) (खरीफ विपणन मौसम)
	1995-96	(19.8.96 तक)
आंध्र प्रदेश	—	36.13
असम	—	0.02
बिहार	नग०	नग०
गुजरात	0.01	—
हरियाणा	31.02	6.87
कर्नाटक	—	0.78
मध्य प्रदेश	1.69	6.84
महाराष्ट्र	—	0.38
उड़ीसा	—	4.53
पंजाब	72.99	34.56
राजस्थान	4.54	0.02
उत्तर प्रदेश	13.02	7.20
पश्चिम बंगाल	—	1.27
दिल्ली	नग०	—
जोड़:	123.27	98.60

नग०—नगण्य:—500 टन से कम।